



# महाराष्ट्र शासन राजपत्र

## असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक २३]

मंगळवार, जुलै १४, २०१५/आषाढ २३, शके १९३७

[पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ३६

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक १४ जुलाई २०१५ ई. को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :-

L. A. BILL No. XXIX OF 2015.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA ENTERTAINMENT  
DUTY, ACT.

विधानसभा विधेयक क्रमांक २९, सन् २०१५।

महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम में अधिकतर संशोधन संबंधी विधेयक ।

क्योंकि राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

सन् १९२३ और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी, जिनके  
का १। कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने  
के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, और इसलिए, महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क (संशोधन) अध्यादेश,  
महा. अध्या. २०१५, १२ जून २०१५ को प्रख्यापित हुआ था ;  
क्र. ११।

(१)

**और क्योंकि** उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम  
तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क (संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाये।  
(२) यह १२ जून २०१५ को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

सन् १९२३ का  
१ की धारा ४  
में संशोधन।

२. महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम (जिसे इसमें आगे “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा ४ सन् १९२३ का १।  
की उप-धारा (३) में “और धारा ५ के” शब्द और अंक अपमार्जित किये जायेंगे।

सन् १९२३ का  
१ की धारा ४ख  
में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ४ख की उप-धारा (४) में, “और निदेश भी दे सकेंगे” शब्दों से प्रारंभ होनेवाले और “उस रकम के डेढ़ गुना” शब्दों से समाप्त होनेवाले प्रभाग के स्थान में “और स्वत्वधारी, इस प्रकार निर्धारित शुल्क की रकम के अतिरिक्त धारा ५ के अनुसार शास्ति का भुगतान करने का भी दायी होगा” शब्द और अंक रखे जायेंगे।

सन् १९२३ का  
१ की धारा ५  
का प्रतिस्थापन।

४. मूल अधिनियम की धारा ५ में यथा निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :—

धारा ४ के  
अननुपालन के  
लिये दंड।

“५. (१) यदि कोई व्यक्ति मनोरंजन के किसी स्थान में प्रवेशित है और धारा ४ के उपबंधों का अनुपालन नहीं करता है, तब मनोरंजन के स्वत्वधारी को जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रवेशित है, मनोरंजन शुल्क, जिसका भुगतान करना होगा, के अतिरिक्त, कलक्टर को प्रत्येक ऐसे अननुपालन के लिये, पचास हजार रुपये के समान शास्ति या ऐसे मनोरंजन शुल्क के दस गुना, जो भी अधिक हो, का भुगतान करने का भी दायी होगा :

परंतु, ऐसे स्वत्वधारी को जब तक सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया नहीं जाता तब तक स्वत्वधारी को ऐसी शास्ति का भुगतान करना आवश्यक है, का कोई आदेश कलक्टर द्वारा पारित नहीं किया जायेगा।

(२) इस धारा के अधीन कलक्टर द्वारा बनाया गया प्रत्येक आदेश, धारा १०क के अधीन अपीलीय होगा।” ।

सन् १९२३ का  
१ की धारा १०क  
में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा १०क की उप-धारा (१) में, “धारा ४ ख के अधीन” शब्दों, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, “या धारा ५ के अधीन आदेश” शब्द और अंक निविष्ट किये जायेंगे।

कठिनाईयों के  
निराकरण की  
शक्ति।

६. (१) इस अधिनियम द्वारा, यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, राजपत्र में, प्रकाशित किसी आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत कोई ऐसे निदेश दे सकेगी जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

परंतु, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात्, ऐसा कोई भी आदेश नहीं बनाया जाएगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

सन् २०१५ का  
महा. अध्यादेश  
क्र. ११ का  
निरसन तथा  
व्यावृत्ति।

७. (१) महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०१५ का महा. अध्यादेश क्र. ११।  
(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत किसी बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत), इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जाएगी।

## उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य ।

महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम (सन् १९२३ का १), राज्य में मनोरंजन के विभिन्न प्रकारों और प्ररूपों पर मनोरंजन शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए उपबंध करता है। उक्त अधिनियम की धारा ५ यह उपबंध करती है कि, यदि, कोई व्यक्ति मनोरंजन के किसी स्थान में प्रवेशित था और धारा ४ के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया था तो मनोरंजन के सत्वधारी को जिसमें ऐसा व्यक्ति के प्रवेशित था तो दोषसिद्धि पर, मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रत्येक अपराध के संबंध में पचास हजार रुपयों से कम न हो इतने जुर्माने से या राजस्व हानि के दस गुना जो भी अधिक हो, दण्डित होगा। तथापि, मैजिस्ट्रेट के समक्ष सत्वधारी की दोषसिद्धि प्रायः समय लेनेवाली और जुर्माने और उसकी वसूली के अधिरोपण में विलंब करनेवाली थी।

२. धारा ४ के उपबंधों के अननुपालन के मामले में तुरंत कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य में उक्त अधिनियम की धारा ५ प्रतिस्थापित करने का प्रस्तावित किया गया था ताकि, मनोरंजन के स्वत्वधारी पर ऐसे अननुपालन के लिए उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, शास्ति अधिरोपित करने के लिये, कलक्टर को सशक्त किया जा सके। उक्त अधिनियम की धारा १०क में यथोचित संशोधन द्वारा धारा ५ के अधीन पारित कलक्टर के ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील करने के लिए भी उपबंध प्रस्तावित किए गए थे।

३. किसी मनोरंजन जिसके संबंध में शुल्क देय है, संबंधी विवरणियाँ न देने के लिये दो विभिन्न शास्तियों को परिहार करने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम की धारा ४ ख की उप-धारा ४ में यथोचित संशोधन करने के लिये प्रस्तावित किया गया था।

४. क्योंकि, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी, जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम (सन् १९२३ का १) में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, २०१५, (सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. ११) १२ जून २०१५ को प्रख्यापित हुआ था।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधान मंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुम्बई,  
दिनांकित ७ जुलाई २०१५।

एकनाथराव खडसे,  
राज्यस्व मंत्री।

**प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन ।**

प्रस्तुत विधेयक में विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ, निम्नलिखित प्रस्ताव अर्न्तग्रास्त है, अर्थात् :—

**खंड ६—**इस खंड के अधीन, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो उसके निराकरण के लिए कोई आदेश जारी करने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई है ।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए, उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप का हैं ।

(यथार्थ अनुवाद)

**डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,**  
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।

**विधान भवन :**  
मुम्बई,  
दिनांकित १४ जुलाई २०१५ ।

**डॉ. अनंत कळसे,**  
प्रधान सचिव,  
महाराष्ट्र विधानसभा ।